सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

कानपुर, गुरुवार, 07 अगस्त, 2025
वर्षः 02, अंकः 210, पृष्ठः 8+4

इनसाइड अधिवक्ता अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी से सनसनी... » Pg 03

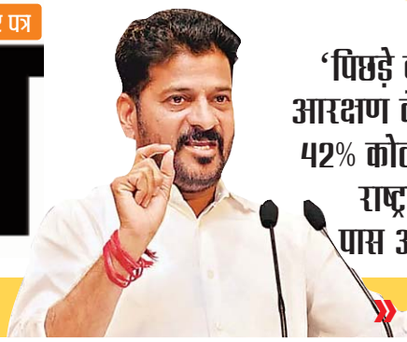

'पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए 42% कोटा बिल राष्ट्रपति के पास अटका'

» Pg 12

पेपर लीक-भ्रष्टाचार के खिलाफ एसएससी उम्मीदवारों का हल्लाबोल

परीक्षा में पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ी और मनमानी कटऑफ से नाराज छात्र

» शिवांक अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया

लखनऊ। देशभर में एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा कराई जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा अब उबाल पर है। दिल्ली, पटना, जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इन छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है और बार-बार पेपर लीक, अनियमित कटऑफ और तकनीकी खामियों ने उनका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बिगाड़ दिया है। सोशल मीडिया पर #JusticeForSSCAspirants, #SSC Scam, #CBIInquirySSC जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जो इस आंदोलन की व्यापकता को दर्शाते हैं। छात्रों के मुताबिक, यह केवल एक परीक्षा की बात नहीं है बल्कि यह आंदोलन उनके आत्मसम्मान, उनके हक और भविष्य के लिए है, जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

तकनीकी गड़बड़ियों ने बढ़ाई मुश्किलें : एसएससी की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में जिस प्रकार की तकनीकी खामियां देखने को मिल रही हैं, उसने पूरी भर्ती प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कई बार बिना किसी कारण के उनकी स्क्रीन अचानक बंद हो गई, सिस्टम हैंग हो गया या पेपर खुद ब खुद ऑटो-समिट हो गया। इससे न केवल उनका कीमती समय नष्ट हुआ बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ा। सबसे गंभीर आरोप ऐजुक्रिटी नामक निजी कंपनी पर लगे हैं, जिसे एसएससी ने परीक्षा संचालन के लिए वेंडर नियुक्त किया था। छात्रों का कहना है कि यह वही कंपनी है जिसे व्यापम घोटाले के दौरान अनियमितताओं के चलते ब्लैकलिस्ट किया गया था। इसके बावजूद एसएससी ने उसे परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी। परीक्षा केंद्रों पर बिजली की समस्या, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा की कमी, और अव्यवस्थित बैठने की स्थिति ने छात्रों की परेशानियों को और बढ़ा दिया।

दिल्ली चलो आंदोलनः लाठीचार्ज से भड़की भीड़

31 जुलाई को देशभर के छात्र और चर्चित शिक्षकों की अगुवाई में 'दिल्ली चलो' आंदोलन के तहत एक ऐतिहासिक प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जिसमें नीतू मैम, अभिनय शर्मा, रजत यादव जैसे शिक्षकों के साथ हज़ारों छात्र एकत्र हुए थे। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया।

छात्रों की मांगेंः पारदर्शिता और न्याय

छात्रों ने अपनी प्रमुख मांगों को स्पष्ट रूप से सामने रखा है, जिनमें सबसे अहम है एसएससी द्वारा नियुक्त ऐजुक्रिटी वेंडर की निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच कराई जाए और उसे तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही सभी भर्तियों की एक पारदर्शी और समयबद्ध टाइमलाइन बनाई जाए ताकि वर्षों तक भटकने की नौबत न आए। छात्रों ने यह भी मांग की है कि परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह नगर या नजदीकी शहरों में ही किया जाए ताकि आर्थिक और मानसिक बोझ कम हो सके।

सीएम योगी का ऐलान

संभल को मिलेगी नई पहचानः 659 करोड़ की सौगात, तीर्थों का होगा पुनरोद्धार

संभल के साथ अन्याय करने वालों को मिलेगी सजा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

संभल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को विकास और धार्मिक पुनर्जागरण की नई राह पर ले जाने का संकल्प दोहराया। बहजोई में 659 करोड़ की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब संभल न सिर्फ तरक्की का प्रतीक बनेगा, बल्कि अपनी आध्यात्मिक विरासत को भी पुनः प्राप्त करेगा।

मुख्यमंत्री ने संभल को भगवान विष्णु के दसवें अवतार 'कल्कि अवतार' का स्थल बताते हुए 68 तीर्थ स्थलों और 19 पवित्र कूपों के पुनरोद्धार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 'हम विरासत के साथ विकास को जोड़कर संभल को उसकी खोई हुई पहचान दिलाएंगे।'

इस अवसर पर उन्होंने संभल संवाद ऐप का उद्घाटन किया, अन्नप्राशन संस्कार कराया, प्रदर्शनी देखी और लाभार्थियों को योजनाओं के तहत चेक, चाबियां और प्रमाण पत्र भी सौंपे।

सीएम ने कहा, 'हम वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि विरासत और आस्था के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। जिन्होंने संभल के साथ पाप किया, अब उन्हें जवाब मिलेगा।'

आजादी का जश्न

बेसिक शिक्षा परिषद के

स्कूलों में गूंजा देशभक्ति का स्वर

हर घर तिरंगा अभियान में बच्चों का उत्साह चरम पर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन दिनों देशभक्ति से ओत-प्रोत रंग-बिरंगे कार्यक्रमों की धूम है। बच्चों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने और तिरंगे को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रहा यह अभियान 8 अगस्त तक जारी रहेगा।बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी 10 विकास खंडों और नगर क्षेत्र के परिषद स्कूलों में तिरंगा रंगोली, तिरंगा राखी निर्माण, चित्रकला, वाद-विवाद, समूह गान और नुक्कड़ नाटकों जैसी विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

विद्यालय परिसर तिरंगे के रंगों से सजे नजर आ रहे हैं। दीवारों और सूचनापट्टों पर देशभक्ति की झलक दिखाई दे रही है, जिससे विद्यालयों का माहौल एक उत्सव में बदल गया है।बच्चों ने देश की सीमाओं की रक्षा में लगे वीर जवानों और पुलिस बलों के नाम भावनात्मक पत्र लिखे हैं और अपने हाथों से बनी तिरंगा राखियाँ उनके लिए तैयार की हैं। विभाग द्वारा ऐसे 200 पत्रों और राखियों को डाक विभाग की मदद से देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात सुरक्षा बलों तक भेजा जा रहा है।

इस अभियान में प्राथमिक विद्यालय सरसौल, बखरिया, गनेशपुर, करबिगवां, टटिया भगवंतनगर, किदवई नगर नवीन, लोधवाखेड़ा, पतरसा, खजुरिया, बौसर समेत कई प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं पूरे उत्साह और गर्व से हिस्सा ले रहे हैं।

कार्यक्रमों को सफल बनाने में खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, एआरपी और एसआरजी की टीमें दिन-रात सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।बच्चों का देश के प्रति यह समर्पण और जज्बा यह दर्शाता है कि तिरंगे के प्रति सम्मान की लौ आने वाली पीढ़ियों में भी प्रज्ज्वलित है।

सरकारी स्कूलों में 18 से 23 अगस्त के बीच होगी सत्र परीक्षा

» अभिभावको को बुलाकर बताई जाएगी बच्चों की प्रगति

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 1.3 लाख बच्चों की सत्रीय (तिमाही) परीक्षाएं अगस्त माह के मध्य में आयोजित की जाएंगी। इस बार बच्चों की पढ़ाई में बेहतरी के लिए परीक्षा के बाद अभिभावकों को स्कूल बुलाकर बच्चों की प्रगति की जानकारी दी जाएगी।

साथ ही उन्हें बच्चों की कमियों से अवगत कराएंगे ताकि वह आगे चलकर इसमें सुधार कर सकें।

आगे होने वाली परीक्षाओं का परिणाम बेहतर हो सके। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि प्रथम सत्रीय परीक्षा 18 से 23 अगस्त के बीच करा लीं जाएं। परीक्षा कक्षावार मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई तक पूरे कराए गए पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी। परीक्षा के लिए प्रधानाध्यापक विद्यालय स्तर पर पेपर तैयार कराकर परीक्षा का आयोजन करेंगे।

कक्षा व विषय शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन कर परिणाम तैयार करेंगे। परीक्षा के पर्यवेक्षण का दायित्व प्रधानाध्यापक व खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। परीक्षा के बाद एक तिथि घोषित कर अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर बच्चों की प्रगति साझा की जायेगी। इसमें अभिभावकों को परीक्षाफल की जानकारी देने के साथ उन्हें उत्तर पुस्तिका भी दिखाई जाएगी। इसके आधार पर परीक्षा में कमजोर छात्र के अधिगम स्तर को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को चिह्नित कर विषय वस्तु तैयार कर क्योंकि अधिगम स्तर में सुधार किया जाएगा। साथ ही शिक्षक अभिभावकों को भी इसमें सुधार के लिए प्रेरित करेंगे।

ऑपरेशन महाकाल में बड़ा एक्शन

अधिवक्ता अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी से सनसनी

- भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे पाक्सो केस में फंसाने का आरोप
- वसूली और जमीन कब्जे के मामलों में भी हो रही है गोपनीय जांच
- पुलिस आयुक्त ने आम जनता से मांगी शिकायतें, कार्रवाई का आश्वासन

अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार करके कोर्ट में लेकर पहुंची पुलिस

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को एक बड़े खुलासे के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर भाजपा नेता रवि सतीजा के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने और 50 लाख रुपये की वसूली करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सतीजा के खिलाफ दर्ज पाक्सो समेत अन्य धाराओं का मुकदमा मनगढ़ंत था, जिसकी झूठी पटकथा महिला और उसके पीछे खड़े लोगों ने मिलकर तैयार की थी। महिला बिहार की रहने वाली है, लेकिन कानपुर में दर्ज इस केस के पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह मुकदमा एक प्रेशर टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि भाजपा नेता पर दबाव बनाया जा सके और उससे भारी रकम वसूली जा सके।

इस साजिश में अधिवक्ता अखिलेश दुबे के साथ-साथ उनके तीन अन्य साथी भी शामिल थे जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद पुष्टि की है कि ये गिरोह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा था। डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि रवि सतीजा से महिला से समझौता कराने के बदले में 50 लाख की डिमांड की जा रही थी, जो एक सोची-समझी वसूली की योजना थी। यह गिरफ्तारी कानपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन महाकाल के तहत की गई, जो ऐसे ही गिरोहों को बेनकाब करने के लिए शुरू किया गया है।

जमीन कब्जा और वसूली में लिप्त दागी वकीलों और वसूली बाजों पर शिकंजा

कानपुर में पिछले डेढ़ साल से भूमाफिया और वसूलीबाज पत्रकारों तथा वकीलों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान चल रहा है। इस कड़ी में ऑपरेशन महाकाल की शुरुआत मंगलवार को पुलिस आयुक्त ने की, जिसका उद्देश्य समाज में भय का वातावरण बनाने वाले तत्वों की पहचान कर उन्हें बेनकाब करना है। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ वकील और मीडिया के लोग गरीबों, महिलाओं और कमजोर तबकों की जमीनों पर कब्जा करने या उनसे धन वसूलने के लिए पुलिस से मिलीभगत कर झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। इन शिकायतों के बाद अब पुलिस ने रणनीति बदलते हुए सीधे आम लोगों से ऐसी जानकारियां मांगी हैं, जिनके आधार पर निष्पक्ष जांच की जा सके।ऑपरेशन के तहत पुलिस अब उन्हीं लोगों को टारगेट करेगी जिनके खिलाफ पीड़ित जनता से सीधी शिकायतें प्राप्त होंगी। अखिलेश दुबे का मामला इस बड़े नेटवर्क की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वकील के खिलाफ पहले से ही जमीनों पर अवैध कब्जे और समझौता कराने के नाम पर लाखों की वसूली जैसे गंभीर मामलों में गोपनीय जांच चल रही है। आने वाले समय में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य वकील, पत्रकार और दलाल भी गिरफ्त में आ सकते हैं। पुलिस का दावा है कि ऑपरेशन महाकाल शहर को वसूलीबाजों से मुक्त कराने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

कानपुर में वर्दी वाली लूट: टीएसआई समेत छह चार्जशीटेड

प्रमुख संवाददाता / स्वराज इंडिया

कानपुर। पुलिसिया वर्दी पहनकर आम लोगों को लूटने वाले एक संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। इस गिरोह में शामिल निलंबित टीएसआई अजीत यादव समेत छह लोगों के खिलाफ रावतपुर पुलिस ने कोर्ट में 250 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। हैरानी की बात यह है कि पूरे गैंग का सरगना टीएसआई नहीं, बल्कि होमगार्ड राजीव दीक्षित निकला, जो फिलहाल जेल में बंद है।

- एसटीएफ बनकर गेस्ट हाउसों में करते थे छापेमारी, मारपीट और लूट की वारदातें
- 250 पेज की चार्जशीट में खुलासा-होमगार्ड राजीव दीक्षित असली मास्टरमाइंड

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य खुद को एसटीएफ अफसर बताकर घरों और गेस्ट हाउसों में धावे बोलते थे। वहां वे न सिर्फ मारपीट करते, बल्कि लोगों पर अनैतिक कार्यों का आरोप लगाकर मोटी रकम ऐंठते थे। गिरोह में शामिल टीएसआई अजीत यादव ट्रैफिक पुलिस लाइन में तैनात था, जबकि बाकी आरोपी अलग-अलग जिलों से थे जिनमें पीआरडी जवान वर्षा चौहान, होमगार्ड राजीव दीक्षित, अरविंद शुक्ल, अनिरुद्ध सिंह और अनुज डंपी यादव शामिल हैं। 8 मई को गिरोह ने शारदानगर में एक महिला के घर पर धावा बोला, उसे पीटा, परिवार का वीडियो बनाया और जेल भेजने की धमकी देकर 1.40 लाख रुपये नकद और 30 हजार रुपये ऑनलाइन वसूल लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 17 मई को केस दर्ज किया और उसी रात पांच आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। टीएसआई अजीत यादव ने 23 मई को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

रावतपुर थाना प्रभारी केके मिश्रा ने बताया कि चार्जशीट में 25 से ज्यादा गवाहों और दर्जनों सीसीटीवी फुटेज को सबूत के रूप में जोड़ा गया है। विवेचना के अनुसार गिरोह की हर कार्रवाई में राजीव दीक्षित और अजीत यादव सबसे आगे रहते थे, जबकि कार भी टीएसआई की इस्तेमाल होती थी। यह मामला न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए शर्मिंदगी का कारण बना, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे कुछ लोग वर्दी का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा की बजाय निजी फायदे और लूट के लिए करते हैं।

65 साल की रमा की पुकार सुन डीएम ने दिखाई संवेदनशीलता

बिल्हौर की वृद्धा को पानी के लिए भटकते देख डीएम ने लिया तत्काल संज्ञान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। उम्र के इस पड़ाव पर जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, तब भी अगर एक वृद्धा रोज पानी के लिए भटकती रहे, तो यह सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक करुण पुकार बन जाती है। बिल्हौर तहसील के ग्राम घिमऊ की 65 वर्षीय रमा गुप्ता की यही पुकार 5 अगस्त को जनता दर्शन में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह तक पहुंची और अगले ही दिन, उनके घर में नल से पानी बहने लगा। गांव में जल जीवन मिशन के तहत अधिकांश घरों में पाइप लाइन बिछ चुकी थी और नल कनेक्शन भी चालू हो चुके थे, लेकिन रमा गुप्ता के घर तक पानी नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कुछ प्रभावशाली लोगों ने जान बूझकर काम में अड़ंगा लगाया। थक-हारकर वृद्धा ने कलेक्ट्रेट का रुख किया और जनता दर्शन में डीएम को पत्र सौंपा। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने न सिर्फ पत्र पढ़ा, बल्कि तत्काल इसे गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अभियंता जल निगम, नायब तहसीलदार बिल्हौर और स्थानीय थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि 24 घंटे के भीतर नल कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन में किसी भी प्रकार की बाधा को शासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

नल लगने के बाद कुछ इस तरह खुश नजर आई रमा।

प्रशासन हरकत में आया और 6 अगस्त को दोपहर तक रमा गुप्ता के घर में नल से पानी बहने लगा। वर्षों की यह प्रतीक्षा जब समाप्त हुई, तो वृद्धा की आंखें भर आईं। यह घटना सिर्फ एक वृद्धा की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अगर जनता की सच्ची पुकार ईमानदारी से प्रशासन तक पहुंचे, तो जवाब भी त्वरित और संवेदनशील मिल सकता है।

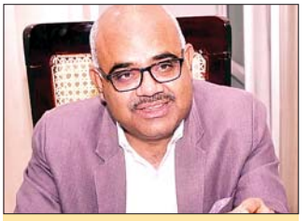

जीतेन्द्र प्रताप सिंह,डीएम कानपुर

तहसील में बैठे अफसरों को नहीं दिखा वृद्धा का दर्द

बिल्हौर। गांव में पाइप लाइन बिछी थी, कनेक्शन भी दिए जा रहे थे, फिर भी रमा गुप्ता को भटकना पड़ा। तहसील के अफसर और स्थानीय कर्मचारी और जल निगम के जिम्मेदार अफसरों ने या तो आंखें मूंद लीं या प्रभावशाली लोगों के आगे मजबूर हो गए। सवाल यह है कि जब एक वृद्धा की आवाज कलेक्ट्रेट तक पहुंची तभी हल निकला। तो क्या तहसील स्तर पर संवेदनशीलता पूरी तरह खत्म हो गई है?

मायावती के निर्देश पर बीएसपी ने तेज की गतिविधियां

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बहुजन समाज पार्टी मिशन 2027 को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के निर्देशानुसार संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज करते हुए बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र को अलग-अलग जोनों में विभाजित कर सेक्टर और बूथ गठन की जिम्मेदारी वरिष्ठ पदाधिकारियों को सौंपी गई है। पार्टी के पुराने और मिशनरी कार्यकर्ताओं फुरकान खान, लईक खां, जयचंद्र, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामदास एवं रवि कुमार गौतम ने गठन प्रकिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मंडल प्रभारी रामशंकर कुरील, जिला कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट विनय कुमार गौतम, विधानसभा प्रभारी जीवन लाल भारती, धर्मेंद्र गौतम एवं विधानसभा अध्यक्ष रमेश पाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष कुलदीप गौतम ने बताया कि संगठन का उद्देश्य है कि हर वर्ग के वंचित, शोषित एवं उपेक्षित समाज की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बसपा को एक बार फिर सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया जाए। इसी को लेकर पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है।

स्वच्छ भारत मिशन

वार्डवार अभियान शुरू, नागरिकों को सिखाया जा रहा गीला-सूखा कूड़ा अलग करना

बिल्हौर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद बिल्हौर द्वारा स्वच्छता को लेकर जन-जागरूकता अभियान में तेजी लाई गई है। बुधवार को पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी सुश्री अंजनी मिश्रा की अध्यक्षता में सोर्स सेग्रीगेशन (कूड़ा पृथक्करण) पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर के विभिन्न वार्डों से आए गणमान्य नागरिक, मोहल्ला समिति के सदस्य, सभासद और पालिका कर्मचारी शामिल हुए। मुख्य रूप से वार्ड संख्या 05, 16, 17 एवं 24 को केंद्र में रखते हुए नागरिकों को गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने और कलेक्शन के समय पृथक रूप से देने की अपील की गई। एसबीएम मंडल कार्यक्रम प्रबंधक पलक शर्मा ने मोहल्ला समिति के सहयोग से नागरिकों को विस्तार से बताया कि सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, फल आदि गीले कूड़े में आते हैं, जबकि प्लास्टिक, पॉलिथीन, रैपर, थैलियां एवं अन्य पैकिंग सामग्री सूखे कूड़े की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता ही सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाएगी। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी सुश्री अंजनी मिश्रा ने नागरिकों से प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग बंद करने और स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की अपील की। पॉलीथीन का प्रयोग न सिर्फ पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, बल्कि नालियों में अवरोध और जलभराव जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न करता है। कार्यक्रम में सभासद मो. शमीम, कांती राठौर, सतेन्द्र पांडेय सहित कई पालिका कर्मी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। जिसमें यह संकल्प लिया गया कि प्रत्येक नागरिक स्वच्छता अपनाएगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा।नगर पालिका के चेयरमैन मो. इखलाक खान ने कहा अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें सिर्फ खुद नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना होगा।

स्वच्छता की शपथ दिलाती ईओ अंजनी मिश्रा व एसबीएम पलक शर्मा।

सम्पादकीय

पहाड़ों के विकास मॉडल पर हो पुनर्विचार

मानसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल व उत्तराखंड में दरकते पहाड़ व रौद्र रूप दिखाती नदियां चिंता बढ़ाने वाली हैं। कुदरत के कहर के सामने इंसान बौना ही नजर आता है। तमाम मुख्य नदियां उफान पर हैं। जगह-जगह भूस्खलन से सड़कें ठप पड़ी हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बीच मलबा व पत्थर गिरने से सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पहले हम गर्मी से त्रस्त होकर बारिश की आस लगाए होते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो स्थितियां डराने वाली हो जाती हैं। निस्संदेह ग्लोबल वार्मिंग संकट के चलते बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। बारिश कम समय में ज्यादा मात्रा में बरसती है। जिससे न केवल पहाड़ों में कटाव बढ़ जाता है बल्कि पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा गिरकर रास्तों व पानी के प्राकृतिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। यह संकट इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमने पहाड़ों को विलसिता का केंद्र बना दिया है। तीर्थाटन अब पर्यटन जैसा हो गया है। पर्यटकों के वाहनों से छोटी सड़कें और पुल दबाव में हैं। नीति-नियंताओं ने पहाड़ों में सड़कों को फोर लेन-सिक्स लेन बनाने का जो उपक्रम किया है, उससे पहाड़ों का नैसर्गिक वातावरण खतरे में है। पहाड़ों के किनारे काटने से भूस्खलन की गति तेज हुई है। गाहे-बगाहे पहाड़ों का मलबा सड़कों पर गिरकर यातायात को अवरुद्ध कर देता है। यात्रियों के जीवन पर हर समय संकट बना रहता है।हिमाचल की ही तरह से कुदरत के कोहराम से उत्तराखंड भी बुरी तरह त्रस्त है। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी व पिंडर आदि नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ने से यात्रा कुछ समय के लिये स्थगित की गई है। बार-बार भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। जगह-जगह सड़कों के कटने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बह गई हैं। बादल फटने की आशंका भी लगातार बनी रहती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री जाने वाले मार्ग जगह-जगह बाधित हैं। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। सामान्य जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई मोटरमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हुए हैं। कई छोटे पुल बह गए हैं। कई निचले स्थानों से लोगों को हटाया गया है। कुल मिलाकर लाखों लोगों को अतिवृष्टि ने बंधक बना दिया है। निश्चित रूप से तेज बारिश और उसके प्रभाव इंसानी नियंत्रण से बाहर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी इलाकों में विकास के मॉडल पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। पहाड़ अध्यात्म के केंद्र भी रहे हैं?

ट्रंप के दबाव में रूसी तेल पर ईयू का खेल

विनय प्रभाकर

यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि सदस्य देशों को अब भारत आदि बाज़ारों से वैसे परिष्कृत ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी, जो मूलतः रूस से आयातित होगा। कहा गया कि भविष्य में परिष्कृत ईंधन आयातकों को प्रमाण देना होगा कि यह रूसी कच्चे तेल से उत्पादित नहीं है। लेकिन ये उपाय कनाडा, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूके और अमेरिका से आयात परलागू नहीं होते हैं।हम इस बात से खुश थे, कि भारत ने प्रसंस्करण किये तेल के निर्यात में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया था। यूरोप वालों को मालूम था कि तेल कहां से आ रहा है, भारत की कौन-सी रिफाइनरी में इनका प्रसंस्करण किया जा रहा है। किन 'शैडो टैंकरों' के ज़रिये इनकी ढुलाई की जा रही है।

लेकिन दोहरे चरित्र वाले यूरोप ने अचानक से पलटी मारी, और भारत की रिफाइनरी के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाकर अमेरिका के समक्ष परमहंस बनने की कवायद शुरू कर दी। वैसे शैडो टैंकर, जो कच्चे या प्रसंस्करित तेल एक महाद्वीप से दूसरे तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में थे, उसके स्वामित्व को लेकर ग्रीस भी जांच के घेरे में है, जो यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। अमेरिका का पिट्ठू और नाटो का सदस्य तुर्की भी इसमें फंसा है, जो रूसी तेल को शैडो टैंकर के ज़रिये यूरोपीय देशों को सप्लाई करता था।छाया टैंकरों के पास वैध कागज़ात, बीमा वगैरह नहीं होते। फ़र्जी बीमा के ज़रिये ये तेल की अवैध ढुलाई करते हैं। ड्रायड ग्लोबल के अनुसार, 'यह बेड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिनकी संख्या 1500 पार है।' यूक्रेन युद्ध के बाद शैडो टैंकर्स सबसे अधिक इस्तेमाल में हैं। तरल माल का बार-बार एक टैंकर से दूसरे टैंकर में स्थानांतरण, डेटा में हेराफेरी करना, और स्वचालित पहचान प्रणाली को ब्लैकआउट करना, ये सब शैडो टैंकर्स संचालकों के लिए साधारण सी बात है। जो पश्चिमी देश अपने आपको परमहंस बताते हैं, रूस ने उन्हीं पश्चिमी देशों की कंपनियों से पुराने जहाज़ ख़रीदे।कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अनुमान है, कि रूस ने 2022 से अपने बेड़े के लिए शैडो टैंकर खरीदने में लगभग 10 अरब डॉलर खर्च किए। यह बेड़ा उन क्षेत्रों के लिए गंभीर पर्यावरणीय और वित्तीय जोखिम को भी दावत देता है, जिन देशों से यह गुजरता है। खासकर किसी रिसाव की स्थिति में उन देशों की जान अटकी रहती है। यूरोपीय संसद की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, '60 प्रतिशत जर्जर जहाजों को पश्चिमी यूरोपीय मालिकों ने बेचा था, जिनमें ग्रीस के टैंकर मालिक अब तक के सबसे बड़े विक्रेता रहे हैं। शेष 40 फीसद ऐसे जंक जहाज भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम सहित कई देशों में फैले हुए हैं।' 10 जनवरी 2025 को अमेरिका ने 183 रूस नियंत्रित जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें से 75 ऐसे टैंकर शामिल हैं, जिनकी पहचान छाया बेड़े के रूप में की गई है। ऐसे जहाजों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) कोड द्वारा की गई है। इन एक्सपायरी डेट वाले जहाजों को कब, और किसने बेचा? उसका पता लगाने के लिए ब्लूमबर्ग डेटा और आईएमओ कोड का उपयोग करते हैं।अब सवाल यह है, कि भारत ने जो तेल अपने यहां आयात किये, और फिर उसका प्रसंस्करण कर विभिन्न देशों को निर्यात किये, क्या उसके लिए शैडो जहाजी बेड़ों का इस्तेमाल हुआ था? हालांकि, भारत के पास कोई छाया बेड़ा नहीं पाया गया है, लेकिन उस पर छाया बेड़े में शामिल टैंकरों के ज़रिए रूसी तेल के परिवहन को सुगम बनाने का आरोप लगाया गया है। दुबई स्थित कुछ भारतीय कंपनियां और संस्थाएं, जिनके भारत से संबंध हैं, रूसी तेल के परिवहन में शामिल रही हैं। भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) ने तेल ढुलाई वाले जहाजों के प्रमाणन में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज़ की है, जिससे चोरी-छिपे तेल भेजने में उनकी संलिप्तता का संदेह बढ़ा है। हालांकि, आईआरएस का कहना है कि जिन जहाजों को वह प्रमाणित करता है।

लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित भारतीय वैश्विक नीति

औजार होने तक सीमित

मदन वर्मा

आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को अपनाया। यानी शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है। जिसकी जड़ें हमारे अतीत में हैं। वहीं लिबर्टी का पाठ पढ़ाने वाली वैश्विक ताकतें ही स्वार्थवश जनतांत्रिक राह त्याग रही हैं। हम दुनिया...

आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को अपनाया। यानी शासन जनता के प्रति उत्तरदायी है। जिसकी जड़ें हमारे अतीत में हैं। वहीं लिबर्टी का पाठ पढ़ाने वाली वैश्विक ताकतें ही स्वार्थवश जनतांत्रिक राह त्याग रही हैं। हम दुनिया के साथ जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन उनकी लोगों की कीमत पर नहीं जिनके पास न आवाज़ है, न वोट, न स्रोत।

स्मृति महज वह नहीं जो कुछ हमें याद रहे। यह उस बारे में है, जो बचना हमें मंजूर नहीं।

उपनिवेशवाद न केवल धन-दौलत लूटता है, बल्कि गरिमा भी खंडित कर देता है। यह पराधीन राष्ट्रों को खुद पर संदेह करना, अपने सहज ज्ञान को नकारना और मान्यता पाने को दूसरे देशों की ओर तकना सिखाता है। भारत के लिए, यह घाव महज चुराए गए अन्न या लूटे गए खजाने का नहीं था। यह मानसिकता में कहीं ज्यादा गहरे तक बदलाव करने वाला रहा - यह धारणा बना देना कि शासन, व्यवस्था और नैतिकता विदेशों की देन है।तथापि, जब स्वतंत्रता मिली, तो भारत ने अपने उत्पीड़कों का अनुकरण नहीं किया। इसने प्रतिशोध को सिद्धांत या बहिष्कार को नीति के रूप में नहीं अपनाया। विभाजन की राख में, भीषण गरीबी और टुकड़े हुए उपमहाद्वीप के बीच, भारत ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया - अपने लोगों पर पूर्णतया भरोसा करने का। केवल पुरुषों पर ही नहीं, पढ़े लिखों पर ही नहीं, केवल पैसे वाले अमीरों पर नहीं बल्कि सभी पर। वयस्क नागरिकों के लिए समान मताधिकार कोई क्रमिक रियायत नहीं थी। यह आधारभूत हक था। अमेरिका द्वारा मताधिकार अधिनियम पारित करने से भी पहले, कई यूरोपीय मुल्कों द्वारा अपने नागरिकों को पूर्ण मताधिकार प्रदान करने से भी पूर्व, भारत अपने प्रत्येक नागरिक को आवाज़ दे चुका था। अपने जन्म के समय से ही, हमारा लोकतंत्र एक उधार लिया हुआ विचार न होकर सभ्यतागत सत्यापना थी।

लेकिन समय का अपना तरीका है नैतिक स्मृति की परीक्षा लेने का। आज, वही शक्तियां जो कभी हमें लिबर्टी का पाठ पढ़ाया करती थी, अब अपनी उन्हीं लोकतांत्रिक नसीहतों पर कायम रहने के लिए हाथ-पैर मार रही हैं। जिन बाज़ारों को उन्होंने कभी मुक्त बनाया था, अब उसी को डिजिटल दीवारों और टैरिफ बैरिकेड्स की ढाल के पीछे महफूज़ बना रही हैं। सबके लिए जिस स्वतंत्रता का कभी वे जोर-शोर से प्रचार करती थीं, अब चुन-चुनकर राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगा रही हैं, इसमें सहयोगियों को छूट तो अन्य को नहीं। करुणा सशर्त बन गयी। व्यापार जोर-ज़बरदस्ती करने का औजार बन गया है।अब यदि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मुक्त बाज़ार पर हमला कर रही हैं, आवाज़ों को दबा रही हैं, टैरिफ का बाजा बजा रही हैं, तुरत-फुरत महानता पाने को, आतंकवादी शासनों से दोस्ती कर रही हैं और अपनी ही दी नैतिक नसीहतों को दरकिनार कर रहीं, तब फिर उन हस्ताक्षरों का क्या मोल, जो वे सकंल्पपत्रों पर और सम्मेलनों में बड़े गर्व से करती हैं?बहुपक्षीय मंचों में, हम देखते हैं कि घोषणाओं को साजिशन कुंद किया जाता है। मानवाधिकारों को लाभ उठाने के औज़ार होने तक सीमित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के वादे दोहराए जाते हैं, लेकिन फिर चुपचाप एक तरफ सरका दिए जाते हैं। शरणार्थियों का अमानवीयकरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर खुलेआम बेजा पुलिसिया दबाव रखा जा रहा है। युद्धों का मूल्यांकन उनकी मानवीय कीमत से नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि हथियार किसके हाथ में है।

बर्रा 8 से जरौली गांव जाने वाली सड़क की मरम्मत शुरू

स्वराज इंडिया की रिपोर्टिंग लाई रंग, पीडब्ल्यूडी ने शुरू की समतलीकरण की कार्रवाई

» स्थानीय नागरिक ने किया था पानी में लेट कर प्रदर्शन

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर के बर्रा 8 क्षेत्र से जरौली गांव की ओर जाने वाली जर्जर सड़क को लेकर स्वराज इंडिया सहित अन्य समाचार माध्यमों की प्रभावशाली रिपोर्टिंग ने आखिरकार असर दिखा ही दिया। शासन के संज्ञान लेने के बाद पीडब्ल्यूडी ने यहां मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है।इस मार्ग की हालत इतनी बदतर थी कि रामगोपाल चौराहा से कटियार मेडिकल स्टोर तक सड़क में गड्ढों के कारण रास्ता ही गायब हो गया था। आवागमन कर रहे राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

जनआंदोलन से जागा सिस्टम

इसी मार्ग पर हीरालाल पटेल इंटरनेशनल स्कूल के पास गड्ढों में साइकिल से गिरकर बेटी अनन्या के चोटिल होने के बाद पिता शालू दुबे ने 2 अगस्त को गड्ढे में लेटकर अनोखा

विरोध दर्ज कराया था। अगले ही दिन पार्षद पति अर्पित यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया।

इस जनदबाव और लगातार मीडिया कवरेज के चलते शासन हरकत में आया और पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता अखंडेश्वर प्रसाद ने डस्ट और गिट्टी डालकर समतलीकरण कार्य शुरू करवा दिया।

बरसात के बाद बनेगी आरसीसी रोड

पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार, बरसात के मौसम में पक्का पैचवर्क संभव नहीं है, लेकिन बरसात के बाद रामगोपाल चौराहा से कटियार मेडिकल स्टोर तक आरसीसी रोड बनाए जाने की योजना है।

यह क्षेत्र करीब 1 किलोमीटर लंबा है, जहां पानी निकासी की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस सड़क को विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत लिया गया है।

नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने सुबह स्वयं इस मार्ग का निरीक्षण किया।

उनके साथ मुख्य अभियंता और नगर निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पाल पेट्रोल पंप तक नाला निर्माण हेतु प्रस्ताव की भी समीक्षा हुई। उम्मीद की जा रही है कि जलनिकासी की समुचित व्यवस्था हेतु यह प्रस्ताव शीघ्र ही मंजूर हो जाएगा।

दक्षिण कानपुर में बीच सड़क पर रोप दिया धान...

» लोग सालों से कर रहे रोड बनाने की मांग, विरोध का तरीका देख हर कोई हैरान

» पीडब्ल्यूडी की सड़कें उखड़ीं और गड्ढों में भरा पानी, मुश्किल में जिंदगानी

कानपुर। सड़कों का गड्ढा मुक्त अभियान सिर्फ आदेशों और कागजातों में देखने को मिल रहा है। हालात यह है कि कानपुर नगर की कई सड़कों की हालत खस्ता है। इन सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऊपर सबकुछ जानने के बाद भी लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बर्रा 8 बसंत पेट्रोल पंप से कटियार मेडिकल स्टोर जरौली फेस 2 नियर आनंद साउथ सिटी तक सड़क अत्यंत ही जर्जर एवं गड्ढायुक्त है। गड्ढे इतने विशालकाय हैं कि आए दिन इनमें ऑटो, रिक्शा एवं अन्य छोटे वाहन पलट जाते हैं और बड़ी गाड़ियों के अक्सर पहिये धंस जाते हैं और बड़े हादसे को दावत देते हैं। रविवार को समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्पित यादव के नेतृत्व में खराब सड़क के खिलाफ लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर धान के पौधे लगाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सालों से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी जाती है, सड़क इतनी जर्जर है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी पहाड़ी एरिया में भ्रमण कर रहे हो। उन्होंने सड़क को ठीक करने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क की हालत इतनी खराब है कि कई लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने में सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस राजमार्ग पर दो दर्जन से अधिक स्कूल स्थित हैं। अर्पित यादव ने कहा कि यह सड़क लम्बे समय से टूटी हुई है पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान शेखर सिंह, छोटे यादव, सतेंद्र सिंह, करन यादव, पुष्पेंद्र सिंह, मानू, अमन यादव, पवन, शुभम शुभी, अभिनव भट्ट, उत्कर्ष, रोहित, सिद्धार्थ, मनोज कुमार, बब्लू आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

PMFME योजना की धीमी रफ्तार पर सीडीओ सख्त, बैंकों को दिए निस्तारण के निर्देश

» 696 के लक्ष्य में सिर्फ 305 प्रस्ताव स्वीकृत, 120 फाइलें अभी भी बैंकों में लंबित

» बिना कारण लंबित आवेदनों पर सीडीओ ने जताई नाराज़गी, दिए सख्त निर्देश

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की धीमी प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. ने सख्त रुख अपनाते हुए बैंकों और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और पात्र आवेदकों को बिना अनावश्यक विलंब के योजना का लाभ मिले।

जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जनपद को 696 आवेदनों का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 305 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। जबकि 120 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित हैं और 317 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इस पर सीडीओ ने नाराज़गी जताते हुए सभी डीआरपी को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने बैंकवार लंबित प्रस्तावों को संकलित कर संबंधित शाखाओं में भेजें और जल्द से जल्द स्वीकृति सुनिश्चित कराएं। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि प्रत्येक डीआरपी को लक्ष्यबद्ध रूप से कार्य करना होगा और प्रस्तावों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बढ़ाया जाए। बैंकों द्वारा बिना ठोस कारण के प्रस्ताव निरस्त करने और महीनों से फाइलें लंबित रखने पर उन्होंने आपत्ति जताई।

उन्होंने बैंकर्स से कहा कि हर आवेदन की निष्पक्षता से जांच करें और किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनागत लाभ से वंचित न किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेजों और प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग मिले।

आया सावन झूम के प्रतियोगिता में छाया सावन का रंग

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित आया सावन झूम के प्रतियोगिता का आयोजन हर्षोल्लास से राज मेमोरियल पब्लिक स्कूल, निराला नगर में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मिसेज इंडिया क्लासिक अंजलि श्रीवास्तव रहीं, जिनके साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सावन थीम पर गीत, संगीत, डांस और मेहंदी जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। डॉ. रीना शर्मा को सावन डांसिंग क्वीन, मुस्कान को मेहंदी क्वीन और 11 वर्षीय मान्यता चक्रवर्ती को सावन रैम्प वॉक विनर घोषित किया गया।

संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिवाकर प्रजापति ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन पीयूष मिश्रा ने किया। निर्णायक मंडल में शकुंतला देवी, संध्या चक्रवर्ती, डॉ. आरती द्विवेदी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

लापरवाही पर चेतावनी:युवा उद्यमी योजना की समीक्षा में सीडीओ सख्त

» कम प्रगति पर दो शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस

» बैंकों को निर्देश : लंबित प्रस्तावों पर जल्द हो कार्यवाही

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन. की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैंकों द्वारा योजना में अपेक्षित प्रगति न दिखाने पर ष्टष्ठह्व ने सख्त रुख अपनाया।

विशेष रूप से बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अकबरपुर और झींझक की शाखाओं पर नाराजगी जताते हुए शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और भविष्य में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

CDO लक्ष्मी एन. ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों से अधिक से अधिक पात्र प्रस्तावों को स्वीकृति देने का निर्देश दिया, ताकि युवा तेजी से स्वरोजगार की ओर बढ़ सकें।

बैठक में यह भी सामने आया कि कई प्रस्ताव ऑनलाइन दर्ज ही नहीं किए जा रहे, और कई महीनों से लंबित फाइलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। CDO ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवेदन का समय पर परीक्षण किया जाए और बिना ठोस कारण किसी भी फाइल को लंबित न रखा जाए।

उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि ग्रामीण और शहरी युवाओं को इस योजना के लिए प्रेरित किया जाए और अधिकतम आवेदन सुनिश्चित किए जाएं, ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।

बारिश बनी कहर: आधी रात ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबी पूरी गृहस्थी

» सिलाई मशीन, कपड़े, बर्तन, अनाज सब हुआ बर्बाद; लेखपाल ने लिया नुकसान का जायजा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले के रसूलाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मकरंदपुर कहिंजरी के मजरा लक्ष्मणपुर गांव में बीती रात एक परिवार पर प्रकृति कहर बनकर टूटी। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते शुक्रवार रात करीब 3 बजे मोर कली पत्नी ओमप्रकाश का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इस हादसे में उनकी पूरी गृहस्थी मलबे में दबकर बर्बाद हो गई।

मोर कली अपने पति और बच्चों के साथ उसी कच्ची छत के नीचे वर्षों से रह रही थीं। बारिश की मार से छत कमजोर हो चुकी थी और बीती रात आई तेज बौछारों ने आशियाने को जमींदोज कर दिया। घटना के समय पूरा परिवार घर में मौजूद था, लेकिन सौभाग्यवश किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ।

घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान मोहनलाल सोनकर मौके पर पहुंचे और तत्काल लेखपाल अजीत कुमार को सूचना दी। लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि मकान के साथ-साथ सिलाई मशीन, बर्तन, कपड़े और कुछ अनाज पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। लेखपाल अजीत कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग की ओर से रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी और नियमों के अनुसार पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए तत्काल राहत दी जाए और पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी योजना के तहत आवास स्वीकृत किया जाए।

कटान बनी काल की दावत: मलासा मार्ग पर मौत मंडरा रही

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा, चांदपुर, बल्हारमऊ देवीपुर मार्ग का निर्माण अभी दो महीने पहले ही लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता और योजना दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। न तो नालियों की समुचित व्यवस्था की गई और न ही सड़क किनारे पटरियों का निर्माण कराया गया। अब लगातार हो रही बारिश ने निर्माण की पोल खोल दी है।

मलासा गांव से पूरब दिशा में अजय सिंह इंटर कॉलेज के पास सड़क के किनारे गहरी कटान हो चुकी है, जिससे मार्ग पर दरारें भी पड़ने लगी हैं।स्थानीय लोगों ने बताया कि कटान की गहराई इतनी अधिक है कि ज़रा सी चूक में वाहन सीधा खंती में गिर सकता है। ये खतरा खासकर बरसात में और भी बढ़ गया है। सड़क किनारे सुरक्षा के कोई उपाय न होने से हादसे की आशंका हर वक्त बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौके से नदारद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी शायद किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेंगे।इसी मार्ग पर स्थित शहीद मूरत सिंह परिषदीय विद्यालय के बाहर भी दुर्घटना का खतरा मंडरा रहा है। गांव के बुजुर्ग श्याम सिंह, बउआ सिंह, जयकारन सिंह आदि ने बताया कि स्कूल में छुट्टी के समय छोटे-छोटे बच्चे तेज़ी से बाहर निकलते हैं और रोड पर सीधा वाहन चालकों के सामने आ जाते हैं। यहां एक स्पीड ब्रेकर की सख्त आवश्यकता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया।गांव के लोगों ने अब मीडिया के माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़क किनारे की कटान को भरा जाए और स्कूल के बाहर ब्रेकर लगाया जाए, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले हालात सुधर सकें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

जनप्रतिनिधियों ने बंद की आंखें, गड्ढों में हिचकोले खा रही जनता

» अकबरपुर, रूरा, तिंगाई सहित क्षेत्र की कई सड़कें बेहाल, सांसद से लेकर स्थानीय विधायक/मंत्री तक कर रही अनदेखी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात की अकबरपुर रनियां विधानसभा में विकास कार्यों की हकीकत जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। गांव से लेकर मुख्य मार्गों तक की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि चलना तो दूर, बचना भी चुनौती बन गया है।रूरा-तिंगाई रोड, रोशनमऊ-मैथा मार्ग और तिंगाई नहर पुल तक की सड़कें इस कदर जर्जर हैं कि कहीं-कहीं से तो सड़क गायब हो चुकी है। बड़े-बड़े गड्ढों ने रास्तों को जानलेवा बना दिया है। हर दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की आंखें अब तक बंद हैं।

यह फोटो तिगांई रोशनमऊ मार्ग की है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कैसे निकलते होंगे

5 साल से खराब, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं!

तिंगाई-रोशनमऊ मार्ग से दो दर्जन से अधिक गांवों का आना-जाना होता है। यह रोड बीते पांच वर्षों से खराब है, लेकिन न पीडब्ल्यूडी हरकत में आया, न कोई योजना बनी। सबसे ज्यादा खराब स्थिति रूरा से तिंगाई नहर पुल तक के हिस्से की है। बारिश ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी है — अब तो पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है।

जनता परेशान, मंत्री और सांसद मूकदर्शक

यह सड़क पीडब्ल्यूडी के अधीन है, लेकिन विभाग की उदासीनता साफ दिखती है। क्षेत्र की विधायक प्रतिभा शुक्ला,

जो कि सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, वे भी आंखें मूंदे बैठी हैं। वहीं क्षेत्रीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले लगातार ई बार सांसद बने हैं, लेकिन जनता को एक ढंग की सड़क तक नसीब नहीं हो सकी। जनता में भारी रोष है, लेकिन शिकायतों के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा।

ओवरब्रिज और टोल से जुड़ा डायवर्जन बना सिरदर्द

रूरा में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के समय भारी वाहनों के लिए डायवर्जन बनाया गया था, जिससे तिंगाई-रोशनमऊ रोड का भारी नुकसान हुआ।

इसके अलावा बारा टोल टैक्स बचाने के लिए कई कमर्शियल वाहन इसी मार्ग से होकर रनियां के रास्ते कानपुर तक जाते हैं, जिससे सड़क और ज्यादा बदहाल हो गई है। खामियाजा भुगत रहे हैं तो गांव वाले, जिनके लिए ये सड़क जीवनरेखा जैसी थी।

जनता का सवाल

स्थानीय लोगों ने स्वराज इंडिया से कहा कि अगर मंत्री और सांसद होते हुए भी हमारी सड़क नहीं बन सकती, तो फिर किससे उम्मीद करें? स्वराज इंडिया न्यूज़ पेपर आपसे वादा करता है कि आपकी आवाज़ हम यूं ही बुलंद करते रहेंगे।

यमुना का पानी घटा, लेकिन दर्द नहीं गया- टूटी नावों, झूठे वादों में डूबे गांव

» प्रभारी मंत्री के वादे हवा हवाई, पीड़ितों को अब तक नहीं मिली स्थायी राहत

» 24 घंटे नाव चलाने वालों को 300 रुपये, ग्रामीण बोले राहत नहीं, दिखावा मिला

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। यमुना का जलस्तर अब कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन भोगनीपुर और सिकंदरा तहसील के बाढ़ग्रस्त गांवों की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ आई, गांव डूबे, सड़क संपर्क टूटा, लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हुए लेकिन प्रशासनिक दावे वही के वही रहे। राहत सामग्री की बजाय बाजार से राशन खरीदकर लाने को मजबूर ग्रामीणों का दर्द इस बार और ज्यादा छलका।

स्वराज इंडिया की टीम जब इन बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंची तो गांववाले खुले शब्दों में बोले साहब! हमें आज तक कुछ नहीं मिला। ये दर्द हम नहीं, हालात खुद कह रहे हैं।

पथार, आढ़न, रसूलाबाद और आसपास के गांवों में दो-दो नावें लगाई गई हैं, जिनसे सैकड़ों लोग पार आते-जाते हैं। हालात ऐसे हैं कि 24 घंटे नाव चलाने वालों को प्रशासन मात्र 300 रुपये प्रतिदिन देता है।

वादों की नाव, राहत के बिना डूबती उम्मीदें

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने भोगनीपुर क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांवों का निरीक्षण किया और लोगों को राहत किट बांटी, लेकिन ग्रामीणों ने उनके वादों पर सीधा सवाल खड़ा किया।

गांव के बुजुर्गों ने बताया कि मंत्री हर साल आते हैं, वादे करते हैं कि ऊंची जगहों पर जमीन देंगे, स्थायी इंतज़ाम करेंगे, लेकिन जब पानी उतर जाता है तो सारे वादे भी साथ बह जाते हैं।

गांव की महिलाएं बोलीं ब्रेकफास्ट किट से नहीं, हमें पुलिया चाहिए। कम से कम आने-जाने की सुविधा तो हो।

ग्रामीणों ने साफ कहा कि 4 पूड़ी और एक चटनी से कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़रूरत है कि बाढ़ से लड़ने का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि हर साल का यह दंश खत्म हो।

अधिकारी स्टीमर से आते, हम टूटी नाव में जान दांव पर लगाते

गांववालों ने यह भी सवाल उठाया कि जब अधिकारी और मंत्री दौरा करते हैं तो वे सुरक्षा युक्त स्टीमर से आते हैं, लेकिन आम ग्रामीणों को टूटी-फूटी नावों में जान जोखिम में डालकर आना-जाना पड़ता है।

अगर कुछ दिन वही स्टीमर हमारे लिए भी लगा दिया जाए, तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, यह बात आढ़न गांव के ग्रामीण सुंदर लाल ने दुख के साथ कही। उन्होंने बताया कि उन्हें न तो राहत सामग्री मिली, न ही कोई स्पष्ट योजना। जानवरों के चारे से लेकर बच्चों के दूध तक, सब कुछ ग्रामीण खुद नाव से लाते हैं, और अगर कोई नाविक मदद कर दे तो ही राहत मिलती है।

क्या बोले डीएम भोगनीपुर?

उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह का कहना है कि राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है, आढ़न गांव में भी टीमें भेजी गई हैं। बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, इसलिए कुछ देरी हो रही है। जो भी ग्रामीण वंचित हैं, उन्हें जल्द मदद मिलेगी।

अयोध्या में बदमाशों पर एसएसपी की सीधी नज़र!

मां मीडिया हाउस वाले राहुल मिश्रा,सट्टेबाज अनवर की खुली हिस्ट्रीशीट

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।अयोध्या में अपराधियों के सुनहरे दिन अब खत्म होते दिख रहे हैं। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में अपराध के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोलने का अभियान पूरे ज़ोर पर है। नकली नोटों के नेटवर्क से लेकर सट्टा, जमीन, शराब और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में लिप्त नामचीन चेहरों की अब साख नहीं, सिर्फ चार्जशीट चल रही है।

ताज़ा कार्रवाई में खुली दो चौंकाने वाली हिस्ट्रीशीट

राहुल मिश्रा, निवासी कंधारी बाज़ार मां मीडिया कंपनी का मालिक खुद को मीडिया वाला बताकर रसूख बटोरने वाला यह शातिर आर्थिक माफिया अब पुलिस रडार पर है। अनवर, निवासी बेनीगंज साहबगंज अयोध्या का कुख्यात जुआ संचालक, जिसकी सट्टेबाजी की महफिलें रात के अंधेरे में सजती थीं, अब हिस्ट्रीशीटर घोषित।

दोनों के खिलाफ संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब तक राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक नकाब इन्हें बचाते रहे। अब एसएसपी ने इन नकाबों को उतार फेंका है। जिनके नाम पर थानों में चाय भी नहीं पी जाती थी, अब उनकी फाइलों में लाल निशान लग चुका है।

सवाल अब सीधा है अगला नंबर किसका?

अयोध्या पुलिस के इस एक्शन मोड से अब जिले के वे 'छुपे चेहरे' भी सहमे हुए हैं जो अब तक रसूख और पहचान के दम पर कानून से ऊपर खुद को समझते रहे।

कई चर्चित नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर समाजसेवा और धर्म के नाम पर पेज सजाते हैं,

लेकिन असल में इनकी फाइल किसी भी दिन खोल दी जा सकती है।जनता को इंतज़ार नहीं अब भरोसा है अयोध्या में अपराध का कोई चेहरा बड़ा नहीं, और एसएसपी की नज़रें अब हर दिशा में पैनी हैं।

एसएसपी अयोध्या

नकली नोट, जमीन घोटाले में फंसा जिला पंचायत सदस्य राजा मानसिंह

नीली टीशर्ट में राजा मान सिंह

» सपा का जिला पंचायत सदस्य या संगठित अपराध का सरगना?

» पत्नी-भाई समेत 8 गिरफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जिसे जनता का सेवक समझा गया, वह निकला संगठित ठगी और नकली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड। समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य राजा मानसिंह उर्फ मान सिंह अब पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर बदमाश। एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर की प्रेसवार्ता में खुलासा हुआ कि राजा मानसिंह पत्नी व भाई के साथ मिलकर जाल बुनता था।

पूराकलंदर पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में राजा मानसिंह समेत कुल 8 लोगों को दबोच लिया गया।

उनके कब्जे से 8 लाख रुपये नगद बरामद हुए हैं। राजा मानसिंह पर नकली नोटों का कारोबार, फर्जी जमीन सौदे, शाइनिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम और पैसे मांगने वालों को धमकाने जैसे संगीन आरोप हैं। शिकायतें जनता दर्शन और जनसुनवाई में पहुंचीं, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की।खास बात ये कि राजा मानसिंह अपने पत्नी और भाई के नाम पर अलग-अलग फर्म चला कर जमीन के सपने बेचता था और निवेशकों को चूना लगाता था। अब पूरा नेटवर्क सलाखों के पीछे है।

एक नेता, आठ गिरफ्तार, सवाल हजार

क्या सपा को नहीं थी अपने जनप्रतिनिधि की असलियत की भनक? क्या यह गिरफ्तारी है या किसी बड़े गिरोह की सिर्फ शुरुआत? जवाब तलाश रही है अयोध्या की जनता, और उठ रही हैं राजनीतिक जिम्मेदारी की भी आवाज़ें।

» (स्वराज इंडिया की खबर का धमाका)

माँ की गोद से छीना गया था नवजात

अब संविदा एएनएम शालिनी सिंह पर कार्रवाई जांच भी जारी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। स्वराज इंडिया की तेज़ और निर्भीक पत्रकारिता का बड़ा असर सामने आया है। पीएचसी बड़ागांव में प्रसव के नाम पर चार हजार रुपये की वसूली कर नवजात शिशु को मां की गोद से छीन लेने वाली संविदा एएनएम शालिनी सिंह पर आखिरकार सीएमओ ने कार्रवाई की है।

स्वराज इंडिया ने 5 अगस्त को इस अमानवीय कृत्य को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सीएमओ डॉ. सुशील कुमार बानियान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शालिनी सिंह का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करते हुए उसके खिलाफ जांच बैठा दी है।

पीड़िता गीता, निवासी राम सरन दासपुर, ने डीएम को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि चार हजार रुपये की मांग पूरी न होने तक एएनएम ने नवजात को जबरन छीन लिया और बाजार से निजी दवाएं भी खरीदवाईं।

यह घटना स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार की

एएनएम ने तोड़ डाली मानवीय संवेदनाओं की सारी हदें

» चार हजार रुपये के लिए नवजात को मां से छीना

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ागांव में कार्यरत संविदा की एएनएम शालिनी सिंह ने मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया। उसने एक प्रसूता से उसके नवजात शिशु को इस लिए छीन लिया कि जबतक चार हजार रुपये नहीं मिलेंगे नवजात शिशु को नहीं देंगे। हार कर परिजनों ने चार हजार रुपये देकर नवजात को एएनएम से छुड़वाया।

प्रसव पीड़िता रुदौली तहसील के राम सरन दासपुर निवासी गीता पत्नी मंजीत ने डीएम से की गई शिकायत में एएनएम शालिनी सिंह पर चार हजार रुपये सुविधा शुल्क की मांग करने व नवजात को छीन लेने व बाजार से दवा की खरीद कराने का आरोप लगाया है। डीएम के निर्देश के बाद सीएमओ ने संविदा एएनएम के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच लगा दी है। तीन सदस्यीय जांच कमेटी मामले की जांच करेगी। जांच टीम में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा वेद प्रकाश त्रिपाठी को अध्यक्ष व सोहावल सीएचसी अधीक्षक डा फातिमा हसन व प्रशासनिक अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र को सदस्य नामित किया गया है।

एक शर्मनाक बानगी है।

अब डॉ. वेद प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति — जिसमें डॉ. फातिमा हसन और बृजेश कुमार मिश्र शामिल हैं — पूरे मामले की जांच कर रही है।

शालिनी सिंह को सीएचसी सुनबा भेज दिया गया है ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो।

स्वराज इंडिया एक बार फिर जन सरोकार की पत्रकारिता में अगुवाई करते हुए अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज़ साबित हुआ है।

यूपी की सियासत में दिखने लगी है बसपा सुप्रीमो की सक्रियता

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर माहौल एक बार फिर से गरमा गया है। अभी तक बीजेपी और सपा ही प्रदेश की राजनीतिक ज़मीन पर एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कुश्तियां लड़ रही थीं लेकिन विगत जुलाई महीने से ही सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती की सक्रियता ने खेल का रंग थोड़ा सा बदल दिया है। काफी अरसे के बाद बसपा सुप्रीमो की सक्रियता ने एनडीए और इण्डिया गठबन्धन, दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। वह आये दिन हर ज़रूरी विषय और मुद्दों पर बोल रही हैं। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आविष्कृत पीडीए के फॉर्मूला पर समाजवादी पार्टी प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी की हितैषी होने का दावा करती है, वहीं बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आये दिन सबका साथ, सबका विकास का नारा देती रहती है। इधर बीच बीजेपी और सपा की मुश्किलें तब बढ़ गयी जब पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने एक बार फिर से कहना शुरू कर दिया है कि बसपा की राजनीति देश के मानवतावादी संविधान के मुताबिक सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही है। साथ ही वे इन दिनों देश-प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर बोल रही हैं।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एक बार फिर से भारत पर टैरिफ बढ़ाने के खेल खेलने पर बहन मायावती ने न सिर्फ इसकी कड़ी निंदा की बल्कि यह भी कहा कि ट्रम्प के इस फैसले ने भारत के साथ विश्वासघात और आघात पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश ब्राजील की तरह ही भारत पर भी अमेरिका ने कुल मिलाकर 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ लगाकर जो हमें आघात पहुंचाने का प्रयास किया है, उसे भारत सरकार ने अपने संयमित बयान में 'अनुचित, अन्यायपूर्ण व अविवेकी' बताया तो है लेकिन हमारे देश की जनता डोनाल्ड ट्रम्प के 'मित्र' देश भारत के प्रति इसे प्रथम दृष्टया विश्वासघाती एवं देश को कमज़ोर करने वाला कदम मानती है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने अप्रत्यक्ष रूप से पक्ष-विपक्ष सहित सभी दलों को नसीहत देते हुये कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए हम सभी को पूरी परिपक्वता दिखाते हुये राजनीतिक स्वार्थ, संकीर्णता तथा मतभेद एवं द्वेष आदि चीजों से ऊपर उठकर दीर्घकालीन रणनीति के तहत देश में पूरे अमन-चैन और कानून व्यवस्था के माहौल के साथ पूरी मुस्तैदी से कार्य करना ज़रूरी है।मानसून सत्र में जारी संसद की चर्चा के दौरान तरह-तरह के वक्तव्य और सवाल-जवाब देखने को मिले और यह दौर अभी भी जारी है। वहीं, सूत्रों की मानें तो आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां पर एस आई आर का मुद्दा काफी जोर-शोर से गरमाया हुआ है। राजद,कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता इस विषय को लेकर आये दिन बीजेपी सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। सांसद राहुल गांधी ने तो बाकायदा अपनी इस पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। ऐसे में बहन मायावती ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा थोपे गये ट्रम्प टैरिफ के दूरगामी असर पर बात करते हुये कहा कि इस समय देश के सामने आयी इस बड़ी चुनौती पर गंभीर चिन्तन की आवश्यकता है और सम्बन्धित विषय पर यदि वर्तमान संसद सत्र में चर्चा हो तो यह जन एवं देशहित में बेहतर होगा। पूर्व सीएम ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें यदि आन्तरिक संकीर्ण मुद्दों में ही अधिकतर उलझी रहेंगी तो फिर यह कैसे संभव हो पायेगा?

बता दें कि हाल ही में एक्स पर बसपा सुप्रीमो का हैंडल काफी सक्रिय दिखाई पड़ा है। गुरुवार को उनके हैंडल से पोस्ट लिखकर डोनाल्ड ट्रम्प के भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने को लेकर कड़ी आलोचना की गयी। इसके अलावा उन्होंने अन्त में एक महत्वपूर्ण बात लिखा जिससे कयास लगाये जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा एक बार फिर पुराने रंग में दिखने लगी है। उन्होंने लिखा, उल्लेखनीय है कि बसपा की राजनीति हमेशा से देश के मानवतावादी संविधान की मंशा के मुताबिक 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की रही है। किन्तु यहां देश में केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच आपसी अविश्वास के कारण जो राजनीतिक टकराव और खींचतान जैसी चीजें लगातार बनी हुई हैं वो अब समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही व्यापक जनहित और देशहित में होगा।

पत्रकार राघवेन्द्र बाजपेई हत्याकांड के दोनों शूटर एनकाउंटर में ढेर

» एसटीएफ ने पिसावा में मुठभेड़ में मारा; पत्नी बोलीं ये न्याय नहीं, सिर्फ खानापूर्ति है

» पुजारी ने मंदिर में आपत्तिजनक हालत उजागर होने पर 4 लाख की सुपारी में कराई थी हत्या

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

सीतापुर। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या में शामिल दो शूटरों को एसटीएफ ने गुरुवार तड़के मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश बाइक से पिसावा क्षेत्र में मौजूद हैं। चेकिंग के दौरान टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक पत्रकार राघवेन्द्र बाजपेई

दोनो हत्यारे

मारे गए बदमाशों की पहचान अटवा गांव (थाना मिश्रिख) के राजू तिवारी उर्फ रिजवान खान और संजय तिवारी उर्फ अकील खान के रूप में हुई। दोनों सगे भाई थे।

इनकी मां मुस्लिम और पिता हिंदू थे, जिसके चलते इनके पास दो अलग-अलग आधार कार्ड और दोहरी पहचान (तिवारी/खान) पाई गई। दोनों पर एक-एक लाख का इनाम था। इनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती जैसे 24 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे।

राघवेंद्र बाजपेयी की पत्नी रश्मि ने एसटीएफ की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हमें कहा गया था कि जब दोषी पकड़े जाएंगे, तो वहीं एनकाउंटर होगा, जहां मेरे पति को मारा गया था, मेरी आंखों के सामने। लेकिन बिना सूचना एनकाउंटर कर दिया गया। यह सिर्फ वाहवाही लूटने की कवायद है, न्याय नहीं।

मंदिर के पुजारी ने दी थी हत्या की सुपारी

हत्या की साजिश कारेदेव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर ने रची थी। राघवेंद्र ने मंदिर में पुजारी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। पुजारी को डर था कि यह बात सार्वजनिक हो जाएगी। इसी डर से उसने शूटरों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। 8 मार्च को दोनों ने हाईवे पर राघवेंद्र की बाइक रोककर उन्हें गोली मार दी थी।

पुलिस इस मामले में पुजारी शिवानंद बाबा समेत तीन आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। अब मुख्य शूटरों के एनकाउंटर के बाद परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है।

अमेरिकी घुड़की से नहीं डरेगा भारत

टैरिफ पर अब आर-पार

पीएम मोदी का संदेश, कान खोलकर सुन लें ट्रंप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर पहली बार बयान दिया है। अमेरिका के 50 फीसदी वाले टैरिफ के जवाब में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है।

अमेरिका की टैरिफवाली घुड़की से भारत डरने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। इस पर पहले विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। अब खुद पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने जो कहा है, उससे साफ है कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से न डरेगा और न झुकेगा। भारत के केंद्र में किसान शुरू से रहा है और उस किसान का हित ही सर्वोपरि है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया। इसके ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा जवाब दिया। बगैर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए इशारों-इशारों में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, वह चुकाएंगे। पीएम मोदी का यह बयान वाशिंगटन को सीधे संदेश के रूप में देखी जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ गया है।

विदेश मंत्रालय दे चुका है करारा जवाब : पीएम मोदी की यह टिप्पणी उस दिन आई, जब एक दिन पहले ही भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया था। जैसे ही बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफवाले आदेश पर साइन किए, वैसे ही भारतीय विदेश मंत्रायल ने फैसले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है।

> "मुझे किसानों के हितों की रक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरियों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है, और मैं उनके कल्याण के लिए जो भी करना पड़े, करने के लिए तैयार हूं। **नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ट्रंप क्यों भड़के

1. अमेरिका के कहने के बावजूद भारत ने रूस से कारोबारी रिश्ता नहीं तोड़ा है।
2. रूसी तेल पर भारत ने अमेरिका को आइना दिखाया।
3. भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान संग सीजफायर का क्रेडिट नहीं दिया
4. पाकिस्तान समेत कई देशों ने ट्रंप के लिए नोबेल की मांग की, मगर भारत ने कह दिया कि क्या वो इसके हकदार हैं।
5. अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस को फाइनेंशियली मजबूत कर रहा है।

ट्रंप के दूत पुतिन से मिले

रूस-यूक्रेन की जंग रुक जाएगी?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में 'महत्वपूर्ण प्रगति' हासिल की है। ट्रंप के अनुसार, बैठक के बाद उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को भी जानकारी दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की पुतिन के साथ बेहद उपयोगी बैठक हुई। सभी इस बात से सहमत हैं कि यह युद्ध अब समाप्त होना चाहिए, और हम आने वाले दिनों और हफ्तों में इस दिशा में काम करेंगे।

जेलेंस्की ने कही ये बात : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि युद्ध का अंत जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय नेता भी इस कॉल में शामिल थे, और उन्होंने यूक्रेन के लिए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद जताया। जेलेंस्की ने कहा, हमने मॉस्को में हुई बातचीत पर चर्चा की।

धरना तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिया धरना

'पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिए 42 फीसदी कोटा बिल राष्ट्रपति के पास अटका'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। रेड्डी ने बुधवार (6 अगस्त, 2025) को दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण विधेयक को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण विधेयक को पारित नहीं किया गया तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे।

सीएम रेवंत रेड्डी ने संसद में बीसी विधेयक पर बहस की मांग करते हुए केंद्र से शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकायों में बीसी समुदाय के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयकों को तत्काल पारित करने का आग्रह किया।

राहुल गांधी के नेतृत्व में हम 42 फीसदी आरक्षण का बिल लाए हैं- मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री ने केंद्र और राष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए कहा, बीसी कोटा विधेयक चार महीनों से राष्ट्रपति के पास लंबित हैं और बार-बार अनुरोध के बावजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक मुलाकात के लिए समय नहीं दिया। रेड्डी ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में जाति जनगणना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के दृष्टिकोण के अनुरूप, हम 42 प्रतिशत बीसी आरक्षण विधेयक लाए हैं। जब तक यह कोटा हासिल नहीं हो जाता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

तेलंगाना के सीएम ने मंत्रियों, विधायकों के साथ जंतर-मंतर पर दिया धरना : इसी मांग को लेकर, दिल्ली के जंतर-मंतर के पास एक विशाल धरना आयोजित किया गया। इस धरने में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रम अर्का, पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, सरकार के कई मंत्री, कांग्रेस विधायक, एमएलसी, बीसी संगठन के नेता और बड़ी संख्या में पार्टी के बीसी नेता शामिल हुए। इस धरने ने बीसी आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की यह मुहिम बीसी समुदाय के अधिकारों के लिए एक सशक्त कदम माना जा रहा है।